

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या-1286 / 2015 / अलवर

मै0 घासोली ट्रेडर्स,
मार्फत-प्रो0 प्रेम चन्द गुप्ता पुत्र श्री शिवदयाल गुप्ता,
जाति-महाजन, निवासी-घासोली, तहसील-किशनगढबास, जिला-अलवर
हाल निवासी-डी-83 हसन खान मेवात नगर, अलवर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, अलवर द्वितीय,
2. मै0 लीलाधर भीमसेन,
मार्फत-प्रो0 विश्वामित्र पुत्र श्री बनवारी लाल,
जाति-महाजन, निवासी-म.नं. 1162, भट्टू मण्डी,
जिला-फरीदाबाद(हरियाणा)

.....अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम-सदस्य

उपस्थित : :

श्री रोहित सोनी,

अभिभाषक

.....निगरानीकर्ता की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा,

उप राजकीय अभिभाषक

..अप्रार्थी संख्या एक की ओर से

श्री अमित कुमार

अभिभाषक

....अप्रार्थी संख्या दो की ओर से

निर्णय दिनांक : 20/06/2017

निर्णय

1. प्रार्थी-निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी कलक्टर (मुद्रांक) अलवर प्रथम (जिसे आगे कलक्टर (मुद्रांक) कहा जायेगा) के द्वारा प्रकरण संख्या 85/15 में पारित निर्णय दिनांक 29.06.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा उन्होंने उप पंजीयक, द्वितीय अलवर द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि लीलाधर भीमसेन मार्फत-प्रो0 विश्वामित्र पुत्र श्री बनवारी लाल, जाति-महाजन, निवासी-म0नं0. 1162, भट्टू मण्डी, जिला-फरीदाबाद (हरियाणा) (विक्रेता) ने अपने स्वामित्व की खरीदशुदा जायदाद पुख्ता गोदाम मय फड, गोदाम नं0 जी बी-39 वाके नवीन कृषि उपज मण्डी प्रांगण, शहर अलवर स्थित जिसका क्षेत्रफल 88.88 वर्गगज ने प्रार्थी घासोली ट्रेडर्स, मार्फत-प्रो0 प्रेम चन्द गुप्ता पुत्र श्री शिवदयाल गुप्ता, जाति-महाजन, निवासी-घासोली, तहसील-किशनगढबास, जिला-अलवर हाल निवासी डी-83 हसन खान मेवात नगर, अलवर (क्रेता) को रू0 15,00,000/- में विक्रय कर, विक्रय लेखपत्र उप पंजीयक अलवर द्वितीय के समक्ष पंजीयन हेतु पेश किया। उप पंजीयक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को पंजीयन क्रमांक 2013006976 दिनांक 05.07.2013 को पंजीबद्ध कर संबंधित पक्षकार को

२१ ✓

लगातार.....2

लौटा दिया। परन्तु आंतरिक लेखा जांच/महालेखाकर जांच दल द्वारा मौका निरीक्षण के पश्चात प्रश्नगत दस्तावेज की कुल मालियत रू0 23,83,797/- मानी गई जिसके आधार पर उप पंजीयक द्वारा धारा 54 के अन्तर्गत प्रार्थी(क्रेता) को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी क्रेता द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर, रेफरेन्स तैयार कर कलक्टर(मुद्रांक) को पेश किया गया। कलक्टर (मुद्रांक) ने प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार करते हुए, प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत उपरोक्तानुसार आंकी जाकर, कमी मुद्रांक रू0 45,469/-, सरचार्ज रू0 4,538/-, कमी पंजीयन शुल्क रू0 8,837/-, शास्ती रू0 14,720/- एवं ब्याज रू0 14,006/- कुल रू0 87,570/- प्रार्थी क्रेता से वसूल करने का आदेश पारित किया। कलक्टर (मुद्रांक) के इस आदेश से व्यथित होकर, प्रार्थी-क्रेता द्वारा यह निगरानी पेश की गयी है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक व 2 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में रेफरेन्स को स्वीकार करने के सम्बन्ध में कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। निर्णय नॉन स्पीकिंग व नॉन रीजण्ड है। निर्णय में तर्क, कारण व विवेचना का अभाव है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान मुद्रांक नियम 2003 के नियम 65 की पालना किये बिना व बिना कोई जांच किए रेफरेन्स स्वीकार किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर रेफरेन्स खारिज किया जावे।

6. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

8. निगरानी में मुख्य आधार यह है कि निर्णय में रेफरेन्स के बिन्दुओं को बिना कोई विवेचना एवं विश्लेषण किये पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में रेफरेन्स को स्वीकार करने के सम्बन्ध में कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। निर्णय नॉन स्पीकिंग व नॉन रीजण्ड है। निर्णय में तर्क, कारण एवं विधिक विवेचना का अभाव है।

कलक्टर (मुद्रांक) अलवर के निगरानीधीन आदेशों के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि कलक्टर (मुद्रांक) ने रेफरेन्स के तथ्यों की विवेचना किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स रेफरेन्स स्वीकार किये जाने का कोई आधार स्पष्ट नहीं किया है व न ही रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में कोई जांच की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरान्त ही उन्हें मानने या न मानने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करते, जिससे अपीलीय अधिकारी के आदेश/निर्णय के विरुद्ध अपील होने पर सम्बन्धित न्यायालय अपना निर्णय पारित करें कि अवर अधिकारी का निर्णय न्याय संगत है अथवा नहीं किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि वह सचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष अभिव्यक्ति दें। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स, कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स (Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किय गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :-

".... To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regular hearing."

"A litigant has legitimate expectatoion of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretation by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally cease. Such is the signifucance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent . Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of corection is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appeaaar to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system." उपरोक्त विधिक धारणा से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है।

9. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में Self valuation(on Presentation) प्रपत्र दिनांक 05.07.2013 में सम्पत्ति को अर्द्धवाणिज्यिक (गोदाम) बताया गया है जिसके आधार पर मूल्यांकन कर दस्तावेज पंजीबद्ध किया गया है। ऑडिट आक्षेप सम्पत्ति को पूर्ण

लगातार.....4

वाणिज्यिक श्रेणी में मानने के संबंध में है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वे रेफरेंस के तथ्यों की जांच करते, सम्पत्ति को वाणिज्यिक श्रेणी में मानने के संबंध में अधिनियम, नियम व विभाग के दिशा निर्देशों के संबंध में विवेचना कर अपना मत प्रकट करते जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने सीधे ही बिना कोई विवेचना विश्लेषण किये निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है।

10. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निगरानीधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया हैं तथा यदि प्रकरण में निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया जाता है तो न्यायिक दृष्टिकोण से प्रार्थी को सुनवाई का भी समुचित अवसर मिल सकेगा।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेचना-विश्लेषण सहित निर्णय पारित नही करने के कारण विधिसम्मत नही होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.07.2017 को पेश हों।

12. निर्णय सुनाया गया।

(²⁰¹⁷नित्यूराम)
सदस्य